



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 240]
No. 240]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 1983/ज्येष्ठ 10, 1905
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 1983/JYAISTHA 10, 1905

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग संकलन के रूप में
रखा जा सके

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मई, 1983

का. आ. 386.—(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./83:—
केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास
मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 134 (अ)/18कक/आई. डी.
आर. ए./79 तारीख 13 मार्च, 1979 द्वारा यथा उपांतरित
आदेश सं. का. आ. 529 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./
74 ता. 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात्
उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, अंतःकरण उद्योग विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार को (जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुन-
निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कहा गया है) (जिसे
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स
इंडिया वेल्डिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपूर, पश्चिमी
बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम
कहा गया है) तारीख 8 सितम्बर, 1974 से पांच वर्ष की अवधि
के लिये प्रबंध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि लोकहित में यह
समीचीन है कि उक्त अधिसूचित आदेश को उपयुक्त पांच वर्ष के
समाप्त होने के बाद प्रभावी बना रहना चाहिये और उसमें 31 मई,
1983 तक की जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, अतिरिक्त अवधि
268 GI/83

(1)

के लिये इसे जारी रखने के लिये समय-समय पर निदेश जारी
किये थे, (देखिये भारत सरकार के औद्योगिक विकास विभाग
सं. का. आ. 512(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./79, तारीख
4 सितम्बर, 1979, सं. का. आ. 749(अ)/18कक/आई. डी. आर.
ए./80, तारीख 5 सितम्बर, 1980, और सं. का. आ. 684(अ)/
18कक/आई. डी. आर. ए./81, तारीख 4 सितम्बर, 1981, सं.
का. आ. 125(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 5 मार्च,
1982, सं. का. आ. 648(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./82
तारीख 4 सितम्बर, 1982, तथा सं. का. आ. 158(अ)/18कक/
आई. डी. आर. ए./83, तारीख 4 मार्च, 1983 ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन
है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति
द्वारा 31 दिसम्बर, 1983 तक की और अवधि के लिए जारी रखा
जाय ;

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधि-
नियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उप-धारा (2)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि
उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी
सम्मिलित है की और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[फा. सं. 2(14)/80-सी.यू.एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY**(Department of Industrial Development)****ORDER**

New Delhi, the 31st May, 1983

S.O. 386(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)/18AA/IDRA/74, dated the 6th September, 1974 as modified by the Order No. S.O. 134(E)/18AA/IDRA/79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued

directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st May, 1983 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 512(E)/18AA/IDRA/79, dated the 4th September, 1979, S.O. 749(E)/18AA/IDRA/80, dated the 5th September, 1980, S.O. 684(E)/18AA/IDRA/81, dated the 4th September, 1981, S.O. 125(E)/18AA/IDRA/82, dated the 5th March, 1982, S.O. 648(E)/18AA/IDRA/82, dated the 4th September, 1982 and S.O. No. 158(E)/18AA/IDRA/83, dated the 4th March, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for further period upto 31st December, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st December, 1983.

[File No. 2(14)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.